



तेज़ी से हरति मंजूरी पर राज्यों की रैंकिंग

प्रलिस के लयि:

पर्यावरण संरक्षण अधनियम, 1986, पर्यावरण प्रभाव आकलन ।

मेन्स के लयि:

पर्यावरणीय मंजूरी (EC) प्रक्रिया और भारत में संबंधति बाधाएँ, भारत में व्यापार करने में आसानी और इससे संबंधति चुनौतियाँ ।

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय ने राज्यों वशेष रूप से राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधकिरणों (State Environment Impact Assessment Authorities) को उस गतिसे रैंक करने का नरिणय लयि है जसि गतिसे वे वकिस परयोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearances) प्रदान करते हैं ।

- **"ईज ऑफ डुइंग बजिनेस" (Ease of Doing Business)** के लयि वशेष रूप से "मंजूरी हेतु समय के आधार पर राज्यों की रैंकिंग" के संदर्भ में की गई कार्रवाई का मुद्दा नवंबर 2021 में उठाय़ा गया था ।
- सभी क्षेत्रों में पर्यावरण मंजूरी दयि जाने की औसत अवधविरष 2019 के 150 दनिों से कम की तुलना में वर्ष 2021 में 90 दनिों से कम है ।

राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधकिरण (SEIAAs):

- SEIAAs बुनयिदी ढाँचे, वकिसातमक और औद्योगकि परयोजनाओं के एक बड़े हसिसे के लयि पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने हेतु ज़मिेदार हैं ।
- इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और लोगों पर प्रस्तावति परयोजना के प्रभाव का आकलन करने और इस प्रभाव को कम करने का प्रयास करना है ।

प्रमुख बदि:

परचिय:

- पर्यावरणीय मंजूरी (EC) के अनुदान में **दक्षता और समयबद्धता के आधार पर** राज्यों को स्टार-रेटिंग प्रणाली के माध्यम से प्रोत्साहति करने का नरिणय लयि गया है ।
- यह मान्यता और प्रोत्साहन के साथ-साथ जहाँ आवश्यक हो, सुधार के लयि प्रेरति करने के तरीके के रूप में अभिप्रेत है ।
- राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधकिरण (SEIAA) जो कम से कम समय में परयोजनाओं को मंजूरी देता है, मंजूरी की उच्च दर तथा कम **"आवश्यक वविरण"** चाहता है, उसे **सर्वोच्च स्थान** दयि जाएगा ।

रेटिंग प्रणाली हेतु पैरामीटर:

- SEIAAs को पाँच मापदंडों पर 0 और 1 के बीच और EC देने के लयि 0 और 2 के बीच वर्गीकृत कयि जाएगा ।
- पैरामीटर हैं:

- परयोजनाओं के लयि EC या संदर्भ की शर्तों (ToR) की मांग वाले प्रस्तावों को स्वीकार करने हेतु एसईआईएए दवारा लयि गए दनिों की औसत संख्या ।
- प्राधकिरण दवारा संबोधति शकियतों की संख्या ।
- उन मामलों का प्रतशित जनिके लयि SEIAAs या 'राज्य वशेषज्ज मूल्यांकन समतियाँ' (SEACs) दवारा साइट का दौरा कयि जाता है ।
- उन मामलों का प्रतशित जनिमें प्राधकिरण परयोजना प्रस्तावकों से एक से अधिक बार अतरिकित जानकारी मांगता है ।
- 30 दनिों से अधिक पुराने नए या संशोधति ToRs चाहने वाले प्रस्तावों के नपिटान का प्रतशित ।

- 120 दिनों से अधिक पुराने, नए या संशोधित EC चाहने वाले प्रस्तावों के नपिटान का प्रतशित ।

■ इस कदम की आलोचना

○ SEIAA को 'रबड़ स्टैम्प प्राधिकरण' बनाना:

- इस तरह की रेटिंग प्रणाली SEIAA को एक 'रबर स्टैम्प अथॉरिटी' बना देगी, जहाँ उसके प्रदर्शन को उस रूप में आँका जाएगा, जहाँ वे पर्यावरणीय गतिवट और सामुदायिक आजीविका को खतरे में डालते हैं ।

○ अनुच्छेद-21 के वरिद्ध:

- यह रेटिंग प्रणाली भी पर्यावरण के कानून के खिलाफ है और संविधान के **अनुच्छेद 21** (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) का उल्लंघन करती है तथा पर्यावरण एवं लोगों की कीमत पर केवल व्यापार को लाभ पहुँचाती है ।

○ SEIAAs के जनादेश को बाधित करना:

- यह कदम **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** और **पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना** के तहत SEIAAs के जनादेश को गंभीर रूप से बाधित करेगा ।
- यह रेटिंग प्रणाली पर्यावरण प्रभाव आकलन की गुणवत्ता में और कमी ला सकती है और यह प्रणाली केवल नयामक प्रक्रिया को कमजोर करती है, जबकि यह तर्क भी सही नहीं है कि मौजूदा प्रणाली के कारण व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि व्यवसायों की खराब स्थिति अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति के कारण है ।

- SEIAAs के प्रदर्शन का आकलन करने हेतु इससे संबंधित मानदंड पर्यावरण संरक्षण जनादेश से अलग होने चाहिये ।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को अपने सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों के लिये वशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से नपिटने हेतु अधिकृत (धारा 3 (3) के तहत) प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है ।

■ भारत में पर्यावरणीय मंजूरी

- भारत में किसी परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी या तो राज्य सरकार और/या केंद्र सरकार द्वारा दी जानी चाहिये ।
- पर्यावरणीय मंजूरी के पीछे मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का कम-से-कम नुकसान सुनिश्चित करना और परियोजना निर्माण के चरण में उपयुक्त उपचारात्मक उपायों को शामिल करना है ।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना हेतु नरिणय लेने के लिये पर्यावरणीय मंजूरी और जन सुनवाई की प्रक्रिया का विवरण शामिल है ।
- यह EIA अधिसूचना सरकार के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र/नजी क्षेत्र दोनों के लिये उनके द्वारा शुरू की गई बड़ी परियोजनाओं हेतु मान्य है ।
- पर्यावरण पर भौतिक-रासायनिक, जैविक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक घटकों के सापेक्ष प्रस्तावित परियोजनाओं, योजना कार्यक्रमों या विधायी कार्यों की संख्या का संभावित प्रभाव पड़ता है ।

आगे की राह:

- हालाँकि पर्यावरण प्रभाव का आकलन पर्यावरण की रक्षा करने तथा पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था, विकास तथा प्रदूषण के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु आवश्यक है, लेकिन इसके दीर्घकालिक चरणों में सुधार करना आवश्यक है क्योंकि यह भारत में व्यापार शुरू करने में एक बड़ी बाधा बन गया है ।
- पछिले कुछ वर्षों में प्रशासनिक और नौकरशाही के मुद्दों ने स्थानीय निवेशकों के लिये भारत में निवेश को कठिन बना दिया है ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस